



10 February, 2024

## अनुदान की अनुपूरक मांगों

**संदर्भ:** वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों की दूसरी किस्त लोकसभा में पेश की।

- सरकार ने चालू वित्तीय अवधि के लिए कुल ₹78,673 करोड़ के व्यय में शुद्ध वृद्धि के लिए लोकसभा से सहमति का अनुरोध किया है।
- अनुदान की अनुपूरक मांगों में ₹2 लाख करोड़ से अधिक का सकल अतिरिक्त व्यय भी शामिल है।
- इस अतिरिक्त व्यय की भरपाई कुल ₹1.21 लाख करोड़ से अधिक की बचत से की जाएगी।
- लोकसभा में प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार, इस प्रस्ताव में कुल ₹78,672.92 करोड़ का शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह भी शामिल है।

### अनुदान की अनुपूरक मांग:

- परिभाषा:** जब चालू वित्तीय वर्ष में किसी सेवा के लिए आवंटित राशि अपर्याप्त होती है, तो संसद उस कमी को पूरा करने के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग को मंजूरी देती है।
- समय:** आवश्यक व्यय के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित करने के लिए इन मांगों को वित्तीय वर्ष के समापन से पहले संसद द्वारा प्रस्तुत और पारित किया जाता है।

### अन्य प्रकार के अनुदान:

- अतिरिक्त अनुदान:**
  - उद्देश्य:** यह नई सेवाओं के लिए वित्त पोषण आवश्यकताओं को संबोधित करता है जिनके लिए मूल रूप से चालू वित्तीय वर्ष में बजट नहीं रखा गया है।

### अधिक अनुदान:

- उद्देश्य:** इसमें उन स्थितियों को शामिल किया गया है जहां वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय किसी विशिष्ट सेवा के लिए आवंटन बजट से अधिक हो जाता है।
- अनुमोदन प्रक्रिया:** लोकसभा में मतदान से पहले, अतिरिक्त अनुदान की जांच की जानी चाहिए और संसद की लोक लेखा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

### प्रत्यानुदान:

- उद्देश्य:** यह भारत के संसाधनों पर अप्रत्याशित मांगों को पूरा करता है, साथ ही तत्काल जरूरतों के लिए एक लचीली फंडिंग व्यवस्था की पेशकश करता है।
- प्रकृति:** अनिवार्य रूप से, यह अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिए गए एक रिक्त चेक के रूप में कार्य करता है।

### अपवादानुदान:

- उद्देश्य:** यह अनुदान वित्तीय वर्ष की नियमित सेवाओं से असंबंधित विशेष उद्देश्यों के लिए आवंटित किया जाता है, जो अक्सर अद्वितीय या असाधारण परिस्थितियों को संबोधित करते हैं।

### सांकेतिक अनुदान:

- उद्देश्य:** यह मौजूदा निधियों के पुनर्विनियोजन के माध्यम से नई सेवाओं के वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करता है।
- राशि और प्रक्रिया:** यह आमतौर पर, एक मामूली राशि (उदाहरण के लिए, 1 रुपया) आवंटित की जाती है, और लोकसभा द्वारा इसकी मंजूरी इच्छित सेवा के लिए धन की उपलब्धता को सक्षम बनाती है।

### संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 115:** यह अनुच्छेद वित्तीय आवंटन की संसदीय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए पूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान से संबंधित प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करता है।
- अनुच्छेद 116:** इस अनुच्छेद के आधार पर लेखानुदान, क्रेडिट वोट और असाधारण अनुदान के लिए संसदीय प्रक्रिया की चिंता, राजकोषीय मामलों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है।
- विनियमन:** ये अनुदान और क्रेडिट तंत्र नियमित बजटीय प्रक्रियाओं पर लागू होने वाली प्रक्रियाओं के समान प्रक्रियाओं द्वारा शासित होते हैं, जो संवैधानिक सिद्धांतों की स्थिरता और अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

## फ्लू-गैस डीसल्फराइजेशन (FGD)

**संदर्भ:** बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने हाल ही में थर्मल पावर संयंत्रों में एफजीडी उपकरण की स्थापना की घोषणा की।

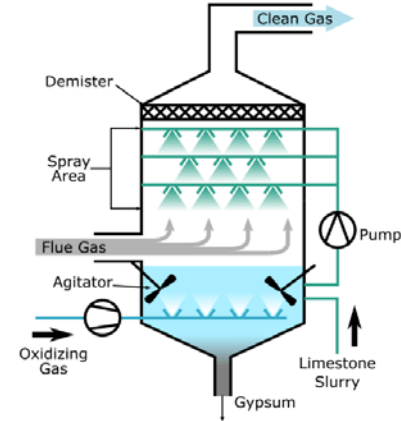
- पूरे भारत में थर्मल पावर प्लांटों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा निर्धारित उत्सर्जन मानदंडों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के निर्देशों का पालन करना होगा।
- बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और झारखंड सहित पूर्वी क्षेत्र के संयंत्र; MoEF&CC द्वारा जारी 5 सितंबर, 2022 की अधिसूचना के अनुसार उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों को उन्नत और स्थापित कर रहे हैं।
- इस समय सल्फर डाइऑक्साइड (SO<sub>2</sub>) उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए, थर्मल पावर प्लांट द्वारा फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (FGD) उपकरण स्थापित किया जा रहा है।

### FGD स्थापना के लिए अनुपालन समयसीमा:

- श्रेणी A:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के 10 किमी के दायरे में या दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 31 दिसंबर, 2024 तक।
- श्रेणी B:** गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या गैर-प्राप्ति शहरों के 10 किमी के दायरे में 31 दिसंबर, 2025 तक।
- श्रेणी C:** अन्य क्षेत्रों में 31 दिसंबर, 2026 तक।

### एफजीडी क्या है?

- बिजली संयंत्रों और औद्योगिक प्रक्रियाओं से सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करके पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन हेतु एफजीडी विधियां अनिवार्य हैं।
- एफजीडी विधि का चुनाव ईंधन के प्रकार, पौधे के आकार और पर्यावरणीय बाधाओं जैसे कारकों पर निर्भर करता है।
- वर्तमान में चल रहे अनुसंधान का उद्देश्य सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन नियंत्रण के लिए एफजीडी दक्षता और लागत-प्रभावशीलता को बढ़ाना है।



### फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) विधियाँ:

- गीली स्क्रबिंग:** फ्लू गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड (SO<sub>2</sub>) के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए क्षारीय मिश्रण का उपयोग किया जाता है, ताकि इसे प्रभावी ढंग से और अपेक्षाकृत कम लागत पर हटाया जा सके।
- स्प्रे-ड्राई स्क्रबिंग:** यह सॉर्बेंट (Sorbent) घोल को बारीक बूंदों में बदल देता है, जिससे गैसीय चरण में SO<sub>2</sub> के प्रतिस्थापन में सुविधा होती है; साथ ही यह स्थान-सीमित या जलीय वातावरण के लिए उपयुक्त होती है।
- गीली सल्फ्यूरिक अम्लीय प्रक्रिया:** फ्लू गैसों से सल्फर को व्यावसायिक गुणवत्ता वाले सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में पुनर्प्राप्त किया जा सकता है, यह सल्फर के प्रतिस्थापन के लिए एक कुशल विधि प्रदान करती है।
- SNOX फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन:** यह SO<sub>2</sub> के प्रतिस्थापन हेतु गीली स्क्रबिंग के साथ NOX हटाने के लिए चयनात्मक उत्प्रेरक कमी (SCR) को एकीकृत करता है, जो प्रदूषण नियंत्रण में भी सहायक है।

## Face to Face Centres





- **डाई सॉबैट इंजेक्शन प्रणाली:** उत्सर्जन से SO<sub>2</sub> और SO<sub>3</sub> को खत्म करने के लिए पाउडर सॉबैट सामग्री को सीधे निकास नलिकाओं में डाला जाता है, जिसका उपयोग अक्सर लागत प्रभावी पेट्रोफिटिंग के लिए किया जाता है।

### इस्पात क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन उपयोग हेतु पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देश

**संदर्भ:** 2 फरवरी, 2024 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत इस्पात क्षेत्र में पायलट हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

#### ➤ सरकारी पहल और बजट आवंटन:

- सरकार ने इस्पात क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2029-30 तक 455 करोड़ रुपये आवंटित किए।
- इस पहल का उद्देश्य निम्नतम मात्रा से आरम्भ करके, अपनी प्रक्रियाओं में हरित हाइड्रोजन को मिश्रित करने में इस्पात संयंत्रों का समर्थन करना है।

#### ➤ योजना का क्षेत्र और उद्देश्य:

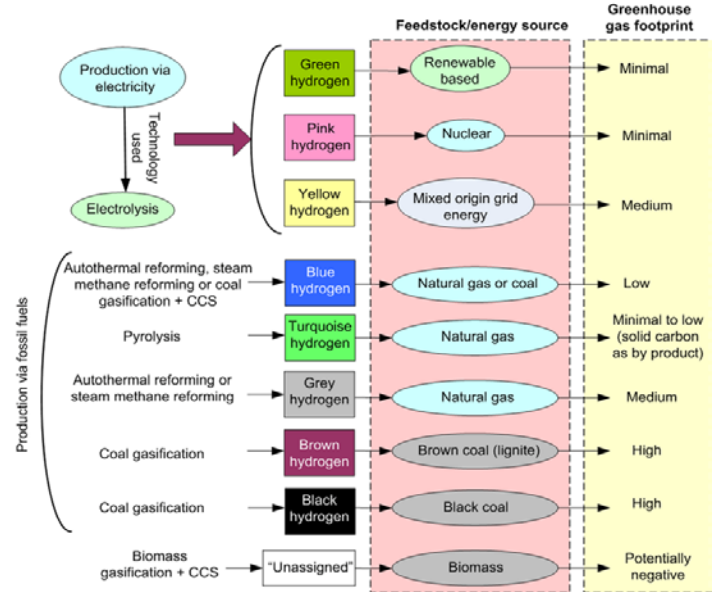
- प्रारंभ में, यह योजना इस्पात प्रक्रियाओं में हरित हाइड्रोजन के अल्पतम प्रतिशत के मिश्रण का समर्थन करती है, हालांकि प्रौद्योगिकी और लागत दक्षता में सुधार के साथ इस मिश्रण में वृद्धि की संभावना है।
- इस योजना का उद्देश्य इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों का विकास, चयन और सत्यापन करना है।
- विशिष्ट उद्देश्यों के लिए डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (DRI) प्रक्रियाओं में; 100% हाइड्रोजन का उपयोग करना, निर्धारित सीमा के भीतर ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन का उपयोग करना, डीआरआई प्रक्रियाओं में हाइड्रोजन के साथ जीवाश्म ईंधन को धीरे-धीरे प्रतिस्थापित करना और लौह तथा इस्पात उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अभिनव तरीकों की खोज करना शामिल है।

#### ➤ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM):

- 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 4 जनवरी, 2023 को लॉन्च किए गए NGHM का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
- इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत में प्रति वर्ष 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन की क्षमता उत्पन्न करना है।
- प्रारंभ में, सरकार का ध्यान केवल उर्वरक और पेट्रोकेमिकल जैसे क्षेत्रों पर था, लेकिन अब भारत में प्रमुख औद्योगिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक स्टील और सीमेंट को भी शामिल करने के लिए इस पहल का विस्तार किया जा रहा है।

#### ➤ वैश्विक और घरेलू पहल:

- वैश्विक स्तर पर, एसएसएबी, वेटनफॉल, एलकेएबी और एच2-ग्रीन स्टील जैसी कंपनियां हाइड्रोजन-आधारित स्टील उत्पादन में अग्रणी हैं।
- भारत ने विशेष रूप से इस्पात क्षेत्र में औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए LEAD-IT पहल के तहत स्वीडन के साथ साझेदारी की घोषणा की है।
- घरेलू स्तर पर, टाटा स्टील और आर्सेलमिजल निप्पोन स्टील इंडिया जैसी कंपनियां इस्पात उत्पादन में हाइड्रोजन के उपयोग की खोज कर रही हैं, जिसकी कुछ परियोजनाएं जमशेदपुर और महाराष्ट्र में अभी चल रही हैं।

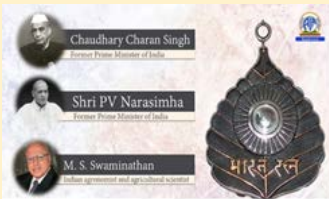


#### ➤ नीतिगत सिफारिशें:

- सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने इस्पात क्षेत्र में प्राकृतिक गैस और हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ईंधन की सिफारिश की और उनकी उत्सर्जन में कमी की क्षमता को रेखांकित किया।
- सिफारिशों में तकनीकी नवाचार और ईंधन स्विचिंग का समर्थन किया गया, विशेष रूप से छोटे पैमाने पर कोयला आधारित डीआरआई-इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) इकाइयों के लिए।

## NEWS IN BETWEEN THE LINES

### भारत रत्न पुरस्कार



हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्रियों पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा की है।

#### भारत रत्न पुरस्कार के बारे में:




- भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
- यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान, कला और साहित्य जैसे क्षेत्रों में राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद (प्रमाण पत्र) और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता है, जिसमें पुरस्कार के साथ कोई मौद्रिक अनुदान नहीं जुड़ा होता है।
- इसकी स्थापना 1954 में की गई थी।
- 1954 में पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर सी.वी. रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे।
- संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार, पुरस्कारों का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- 2024 में, पूर्व प्रधानमंत्रियों पी. वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, हरित क्रांति के प्रणेता एम. एस. स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी सहित पांच लोगों को भारत रत्न मिलेगा।

## Face to Face Centres





10 February, 2024

<p><b>किलकारी कार्यक्रम</b></p> 	<p>हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्रीगण ने वर्चुअल माध्यम से गुजरात और महाराष्ट्र में स्थानीय भाषा में लाभार्थियों के लिए किलकारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। <b>किलकारी कार्यक्रम के बारे में:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>किलकारी कार्यक्रम एक मोबाइल स्वास्थ्य (एम-हेल्थ) पहल है जो गर्भवती और नई माताओं को निःशुल्क, साप्ताहिक ऑडियो संदेश प्रदान करती है।</li> <li>ये संदेश गर्भावस्था, प्रसव और शिशु देखभाल के बारे में जानकारी देते हैं।</li> <li>प्रारंभ में, इस कार्यक्रम को 15 जनवरी, 2016 को डिजिटल भारत पहल के एक भाग के रूप में गर्भवती और नई माताओं के लिए शुरू किया गया था।</li> <li>यह कार्यक्रम हिंदी, भोजपुरी, उड़िया, असमिया, बंगाली और तेलुगु सहित छह भाषाओं में उपलब्ध है।</li> <li>यह वर्तमान में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित है और नौ अन्य राज्य इसमें शामिल होने की प्रक्रिया में हैं।</li> <li>यह कार्यक्रम आशा कार्यकर्ताओं (आशा) के लिए मुफ्त ऑडियो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है।</li> </ul>
<p><b>छद्म उपग्रह</b></p> 	<p>हाल ही में, बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं (NAL) ने सौर ऊर्जा से चलने वाले "छद्म उपग्रह" के पहले परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। <b>छद्म उपग्रह के बारे में:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>छद्म उपग्रह या HAPS (High Altitude Platform Station) एक नई पीढ़ी का मानव रहित हवाई वाहन (UAV) है जो भारत की सीमा क्षेत्रों में निगरानी और निगरानी क्षमताओं को काफी बढ़ा सकता है।</li> <li>यह जमीन से 18-20 किमी की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जो कि वाणिज्यिक हवाई जहाजों द्वारा प्राप्त ऊंचाई से लगभग दोगुना है।</li> <li>यह बैटरी से चलता है और सीमित समय के लिए हवा में रह सकता है और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों को स्कैन कर सकता है।</li> <li>हालांकि, नासा लंबे समय से अपने पाथफाइंडर श्रृंखला के विमानों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले इंजनों का उपयोग कर रहा है।</li> <li>"HAPS आपदा की स्थितियों में भी बहुत उपयोगी हो सकता है। इसका उपयोग दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल संचार नेटवर्क प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है, यदि किसी आपदा के कारण सामान्य नेटवर्क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।</li> </ul>
<p><b>सुखियों में स्थल</b></p> <p><b>सूडान</b></p>	<p>हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र बाल संस्था (यूनिसेफ) ने चेतावनी दी है कि इस साल सूडान में कम से कम 700,000 बच्चे कुपोषण के सबसे खराब रूप से पीड़ित हो सकते हैं और हजारों की मौत हो सकती है। <b>सूडान (राजधानी: खार्तूम)</b> <b>अवस्थिति :</b> क्षेत्रफल के हिसाब से अल्जीरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बाद अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश सूडान, पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित है। <b>राजनीतिक सीमाएँ:</b> सूडान की सीमाएँ इरिट्रिया (पूर्व), लाल सागर (पूर्वोत्तर), चाड (पश्चिम), मिस्र (उत्तर), लीबिया (उत्तर पश्चिम), दक्षिण सूडान (दक्षिण), इथियोपिया (दक्षिण-पूर्व) और मध्य अफ्रीकी गणराज्य (दक्षिण-पश्चिम) से लगती हैं। <b>भौगोलिक विशेषताएँ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>सबसे ऊँचा स्थान: मर्रा पर्वत</li> <li>सबसे लंबी नदी: नील नदी (दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है)</li> <li>नील नदी की सहायक नदियाँ: सफेद नील, नीली नील और अटबारा नदियाँ</li> <li>खनिज संसाधन: अभ्रक, क्रोमाइट, कोबाल्ट, तांबा, सोना, ग्रेनाइट, जिप्सम, लोहा, कैओलिन, सीसा, मैंगनीज, अभ्रक, प्राकृतिक गैस, निकल, पेट्रोलियम, चांदी, टिन, यूरेनियम और जस्ता</li> <li>जलवायु: उष्णकटिबंधीय</li> <li>गृहयुद्ध के लिए कुख्यात क्षेत्र: दारफूर क्षेत्र</li> </ul> 

## POINTS TO PONDER

- हाल ही में ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व और कवल टाइगर रिजर्व के बीच कॉरिडोर क्षेत्र को संरक्षण रिजर्व के रूप में किसने मंजूरी दी? - तेलंगाना राज्य वन्यजीव बोर्ड (SBWL)
- रूसी सेना ने हाल ही में कीव में एक लक्ष्य को भेदने के प्रयास में कौन सी मिसाइल लॉन्च की? - 3एम22 जिरकोन या एसएस-एन-33
- हाल ही में किस बाघ अभयारण्य से एक बाघ भटककर हरियाणा के एक गाँव में आ गया? - सरिस्का टाइगर रिजर्व
- हाल ही में चिनाब नदी का सफल डायवर्जन कहाँ किया गया? - जम्मू एवं कश्मीर
- हाल ही में भारतीय प्रे वुल्फ को कहाँ देखा गया, जो लगभग दो दशकों में इस क्षेत्र में पहली बार देखे जाने की पुष्टि है? - राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (एनसीएस)

## Face to Face Centres

